

सम्पूर्ण-संक्षिप्त-समर्थ

CURRENT AFFAIRS गुरु

UPSC/State PSC परीक्षा की तैयारी करने वाले हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए



1st October 2022



FOR DAILY FREE CURRENT AFFAIRS
Follow Our Youtube Channel

 Guru Deekshaa Hindi



INDEX

DAILY CURRENT AFFAIRS NOTES

1st October 2022

1. - ताज महल:	3
(i) के बारे में:	3
(ii) ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन की स्थिति और प्रदूषण में वृद्धि:	3
2. - सिम्फनी:	4
(i) के बारे में:	4
3. - जलदूत ऐप:	4
4. - पारिस्थितिकीय अर्थव्यवस्था:	5
(i) अन्य विवरण:	5
संपादकीय विश्लेषण	6
1. मसौदा दूरसंचार विधेयक, 2022:	6
(i) के बारे में:	6
(ii) ओटीटी का विनियमन:	6
(iii) लाइसेंसधारियों द्वारा भुगतान करने में विफलता:	6
(iv) भारतीय दूरसंचार उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है?	7



- (v) चुनौतियां: 8
- (vi) ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म वास्तव में क्या हैं? 8
- (vii) आगे का रास्ता: 8

2. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ: 9

- (i) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या कार्य करता है? 9
- (ii) सीडीएस का क्या मतलब है, बिल्कुल? 9
- (iii) सीडीएस भूमिका पर पुनर्विचार क्यों? 10
- (iv) थिएटर कमांड की क्या स्थिति है? 10
- (v) आगे का रास्ता: 11





1. - ताज महल:

GS I

विषय→भारतीय संस्कृति

➤ संदर्भ:

- ताजमहल की जटिल जाली और अलंकरण जैसे स्थापत्य चमत्कार सर्वविदित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नियमित रूप से ताजमहल की विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से अपर्याप्त सुरक्षा की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

के बारे में:

- अपनी पत्नी मुमताज़ महल के सम्मान में, मुगल सम्राट शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण किया, जो सफेद संगमरमर से बना एक ढांचा है। यमुना नदी के किनारे स्थित है।
- यह अपनी ऊंचाई पर मुगल वैभव और वास्तुकला के एक महान उदाहरण के रूप में भी कार्य करता है।
- 1631 और 1648 ईस्वी के बीच ताजमहल को बनाने में कुल 17 साल लगे।

औद्योगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल करें या स्थानांतरित करें।

- 2010 में जारी एक राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के आकलन के अनुसार, पानी और वायु प्रदूषण (एनईईआरआई) के कारण प्रतिष्ठित ताजमहल अभी भी खतरे में है। टीटीजेड क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के कई सरकारी प्रयासों के बावजूद, यह अभी भी मामला था।

• स्रोत→हिन्दू

ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन की स्थिति और प्रदूषण में वृद्धि:

- राष्ट्रीय सरकार ने एमसी मेहता मामले (1996) में स्मारक को प्रदूषण (टीटीजेड) से बचाने के लिए ताज के चारों ओर 10,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन बनाया।
- इसके अलावा, इसने क्षेत्र में काम करने वाली 292 फर्मों को निर्देश दिया कि क्या वे प्राकृतिक गैस को अपने



2. - सिम्फनी:

GS I

विषय→भारतीय संस्कृति:

➤ संदर्भ:

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय 27 सितंबर, विश्व पर्यटक दिवस पर ऑनलाइन सम्मेलन "सिम्फनी" प्रायोजित कर रहा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के पर्यटन व्यवसाय को आगे बढ़ाने और पूर्वोत्तर भारत की अप्रयुक्त सुंदरता पर ध्यान आकर्षित करने की रणनीति बनाना है।
- भारत के उत्तर पूर्व को प्राकृतिक सुंदरता, विविध सभ्यताओं और प्राकृतिक संसाधनों के धन के अपने अद्वितीय संयोजन के लिए "ट्रैवलर्स बेरोज़गार स्वर्ग" के रूप में जाना जाता है।

के बारे में:

- सरकारी आंकड़ों (भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022) के अनुसार, 2020 में 2.74 मिलियन विदेशी पर्यटकों ने भारत का दौरा किया, और 2021 में 1.52 मिलियन ने ऐसा किया।
- 2021 में, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश, कनाडा, नेपाल, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया शीर्ष 15 देश थे, जहां से आगंतुकों ने भारत की यात्रा की।
- 2019 में, 10.93 मिलियन विदेशी आगंतुकों ने देश में प्रवेश किया।
- स्रोत→हिन्दू

3. - जलदूत ऐप:

GS III

विषय→पर्यावरण संरक्षण

- संदर्भ: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्राम रोजगार सहायक को चयनित समुदायों में वर्ष में दो बार चयनित कुओं के भूजल स्तर को मापने के लिए इस ऐप को विकसित किया है।
- डेटा का उपयोग ग्राम पंचायत विकास योजना और महात्मा गांधी नरेगा (GPDP) के लिए भूजल वृद्धि परियोजनाओं को बनाने के लिए किया जाएगा।

- स्रोत→हिन्दू



4. - पारिस्थितिकीय अर्थव्यवस्था:

GS III

विषय→पर्यावरण संरक्षण

➤ संदर्भ:

- ओडिशा के नयागढ़ में कोडलपली, सिंधुरिया और अन्य गांवों की महिलाओं द्वारा एक हरित अर्थव्यवस्था पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जाएगा। ये महिलाएं जंगलों को घर कहती हैं।
- आदिवासी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक गैर-लाभकारी संस्था वसुंधरा की मदद से, उन्होंने वर्षों से ब्लॉक और जिला स्तर पर ग्राम संरक्षण समितियों का एक संघ बनाया है। गांवों और अन्य मुद्दों के बीच असहमति को निपटाने के लिए अधिकारी हर महीने मिलते हैं। अधिकांश अधिकारी महिलाएं हैं।

अन्य विवरण:

- वन का उपयोग करने के नियम, जो मानसून के दौरान चराई पर रोक लगाते हैं, रविवार को हरे पेड़ों को काटते हैं, और गांव के सदस्यों के अलावा किसी और के द्वारा बांस और केंदु (या बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तेंदू पत्ते) जैसे छोटे वन उत्पादों को इकट्ठा करने के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। स्थानीय लोग।
- यह विशाल प्रयोग अब एक नए चरण में आगे बढ़ गया है। वर्षों के संघर्ष के बाद नवंबर 2021 में 24 समुदायों को आखिरकार सांप्रदायिक वन अधिकार मिल जाएंगे। 2006 के वन अधिकार अधिनियम में एक प्रावधान है जो समुदायों को सार्वजनिक स्वामित्व वाली वनभूमि के

एक हिस्से का एकमात्र अधिकार प्रदान करता है जिसका ऐतिहासिक रूप से संसाधन कटाई और संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है।

- राज्य का पहला इको-गांव नयागढ़ जिले का एक सादा समुदाय मुदुलिगड़िया था, जो पहले ही कुख्यात हो चुका था।

• स्रोत→हिन्दू



संपादकीय विश्लेषण

1. मसौदा दूरसंचार विधेयक, 2022:

के बारे में:

- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 और द टेलीग्राफ वायर्स (गैरकानूनी संरक्षण) अधिनियम, 1950 तीन स्वतंत्र कानून हैं जो अब दूरसंचार उद्योग को नियंत्रित करते हैं। प्रस्तावित विधेयक इन कानूनों को समेकित करता है।
- ट्राई प्राधिकरण का कमजोर होना: दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अधिकार को कम करने का भी सुझाव दिया है जब सेवा प्रदाताओं को नए लाइसेंस देने की बात आती है।

ओटीटी का विनियमन:

- व्हाट्सएप कॉल, फेसटाइम, गूगल मीट और अन्य सहित इंटरनेट-आधारित और ओवर-द-टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं को सरकार द्वारा दूरसंचार सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- दूरसंचार उद्योग की यह लंबे समय से मांग थी कि खेल का मैदान समतल किया जाए। ओटीटी प्लेटफॉर्म को वर्तमान में सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दूरसंचार फर्मों को अवश्य करना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, ओटीटी और इंटरनेट आधारित संचार को सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी यदि उन्हें दूरसंचार सेवाओं के दायरे में शामिल किया गया हो।

- वापसी का प्रावधान: दूरसंचार मंत्रालय ने एक प्रावधान रखा है जो उस स्थिति में भुगतान वापस कर देगा जब किसी दूरसंचार या इंटरनेट प्रदाता ने अपना लाइसेंस छोड़ दिया हो।

लाइसेंसधारियों द्वारा भुगतान करने में विफलता:

- सरकार ऐसी राशियों के भुगतान को स्थगित कर सकती है, कुछ या सभी देय राशियों को शेयरों में परिवर्तित कर सकती है, देय राशियों को बट्टे खाते में डाल सकती है, या भुगतान चूक की स्थिति में और वित्तीय तनाव, उपभोक्ता हित जैसी असाधारण परिस्थितियों में भुगतान से राहत प्रदान कर सकती है। क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, या विश्वसनीयता और दूरसंचार सेवाओं की निरंतर आपूर्ति बनाए रखना।
- दिवालिया होने की स्थिति में, एक निश्चित संगठन को आवंटित स्पेक्ट्रम सरकारी स्वामित्व में वापस आ जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार कोई भी अतिरिक्त कार्रवाई कर सकती है जो आवश्यक हो सकती है, जिसमें लाइसेंसधारी या असाइनी को स्पेक्ट्रम का उपयोग जारी रखने की अनुमति देना शामिल है, जैसा कि आवश्यक हो सकता है।
- इस प्रस्ताव (TDF) में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) का नाम बदलकर टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड कर दिया जाएगा।
- यूएसओ फंड का निर्माण दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के वार्षिक राजस्व से होता है। टीडीएफ के लिए प्राप्त किसी भी फंड के लिए भारत की संचित निधि को सबसे पहले क्रेडिट प्राप्त होगा।



- इस पैसे का इस्तेमाल शहरी, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह नई संचार सेवाओं की शुरुआत को बढ़ावा देगा और नई दूरसंचार सेवाओं में कौशल विकास और अनुसंधान में मदद करेगा।

भारतीय दूरसंचार उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है?

वर्तमान स्थिति:

- 2022 तक 1.17 बिलियन ग्राहकों के साथ, भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार उद्योग है। भारत में कुल टेलीघनत्व 85.11 प्रतिशत है।
- पिछले कुछ वर्षों में उद्योग का तेजी से विस्तार मुख्य रूप से कम कीमतों, बढ़ी हुई पहुंच, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी), 3 जी और 4 जी कवरेज का विस्तार, और ग्राहक उपयोग पैटर्न में बदलाव से हुआ है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह के मामले में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग, दूरसंचार क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से 2.2 मिलियन नौकरियों और अप्रत्यक्ष रूप से 1.8 मिलियन नौकरियों का समर्थन करता है।
- 2014 और 2021 के बीच दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश करने वाले FDI की मात्रा 2002 और 2014 के बीच 8.32 बिलियन अमरीकी डालर से 150% बढ़कर 20.72 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई।
- दूरसंचार उद्योग में, वर्तमान में स्वचालित पद्धति के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।
- भारत में 2025 तक 920 मिलियन अद्वितीय मोबाइल ग्राहक होने का अनुमान है, जिसमें 88 मिलियन 5G कनेक्शन शामिल हैं, जो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बनाता है। पहल: दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के उत्पादन के लिए 12,195 करोड़ रुपये की आत्मनिर्भर उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत पीएलआई योजनाएं भारत अभियान का हिस्सा हैं। वर्तमान पीएलआई योजना की डिजाइन आधारित निर्माण योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोत्साहन को अलग रखा गया है।
- दूरसंचार क्षेत्र में सुधार: दूरसंचार क्षेत्र के भीतर तरलता में सुधार और वित्तीय तनाव को कम करने के लिए, 2021 में व्यापक संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधार लागू किए गए थे।
- भारत नेट नामक एक परियोजना 178,247 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल स्थापित हैं, जिनमें से 161,870 सेवा के लिए तैयार हैं। सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों की कुल संख्या अब 166,088 हो गई है, जिनमें से 4,218 को सैटेलाइट मीडिया के माध्यम से जोड़ा गया था।
- ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं के विकास में तेजी लाने के लिए, प्रधान मंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-डब्ल्यूएनआई) पूरे देश में स्थित सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) के माध्यम से मुफ्त सार्वजनिक वाई-फाई प्रदान करता है।



चुनौतियां:

- प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व में गिरावट (एआरपीयू): भारतीय दूरसंचार उद्योग एआरपीयू में गंभीर और निरंतर कमी के परिणामस्वरूप राजस्व बढ़ाने का एकमात्र तरीका समेकन पर विचार कर रहा है, जो मुनाफे में गिरावट और कुछ मामलों में, महत्वपूर्ण नुकसान के साथ मिलकर है।
- टेलीकॉम से लगभग 92,000 करोड़ रुपये की समायोजित सकल आय एकत्र करने के लिए 2019 में सरकार के अनुरोध को स्वीकार करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनकी चिंता को और बढ़ा दिया है।
- स्पेक्ट्रम की सीमित उपलब्धता चीन और यूरोपीय देशों की तुलना में उपलब्ध स्पेक्ट्रम की मात्रा क्रमशः 40% और 50% से कम है।
- कम ब्रॉडबैंड पैठ: देश की कम ब्रॉडबैंड पहुंच चिंता का कारण है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) में दिए गए ब्रॉडबैंड पर एक श्वेत पत्र के अनुसार, केवल 7% भारतीयों की इंटरनेट तक पहुंच है।
- व्हाट्सएप, ओएलए और अन्य जैसे ओवर द टॉप (ओटीटी) एप्लिकेशन के लिए टेलीकॉम कंपनी की सहमति या अनुबंध की आवश्यकता नहीं होती है। इससे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का राजस्व प्रभावित होता है।
- दूरसंचार उपकरणों पर रखी गई मांगों में भारी बदलाव जो पूरे सिस्टम को मुख्य सर्वर से उपयोगकर्ता तक जोड़ने में मदद करते हैं।

ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म वास्तव में क्या हैं?

- ओटीटी, या ओवर-द-टॉप, प्लेटफॉर्म ऐसी कंपनियां हैं जो ऑडियो और वीडियो सामग्री को होस्ट और स्ट्रीम करती हैं। उदाहरणों में नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, हॉटस्टार आदि शामिल हैं। इन कंपनियों ने शुरू में कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम किया, लेकिन जल्द ही अपनी वेब सीरीज, फीचर फिल्मों, वृत्तचित्रों और लघु फिल्मों के निर्माण और रिलीज के लिए इसका विस्तार किया।
- ये प्लेटफॉर्म विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रदान करते हैं और उपयोगकर्ताओं को उनके पूर्व प्लेटफॉर्म उपयोग के आधार पर सामग्री की अनुशंसा करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करते हैं।
- अधिकांश ओटीटी प्लेटफॉर्म अक्सर प्रीमियम सामग्री के लिए मासिक सदस्यता शुल्क लेते हैं जो आमतौर पर अन्य सामग्री को मुफ्त में पेश करते समय कहीं और उपलब्ध नहीं होता है।

आगे का रास्ता:

- ग्राहकों को बेहतर और सुविधा संपन्न सेवा प्रदान करने के लिए नई सुविधाओं और तकनीकों का लाभ उठाने के लिए, भारत में दूरसंचार उद्योग को कई बाधाओं को दूर करना होगा, जैसे पर्याप्त मात्रा में स्पेक्ट्रम को संरक्षित करना और नई तकनीक को अपनाने में तेजी लाना।
- मसौदा दूरसंचार विधेयक 2022 ने इन मुद्दों को संबोधित किया और टिप्पणी के लिए उपलब्ध है, जो दूरसंचार के क्षेत्र में भारत के भविष्य के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित करने में मदद करेगा।



2. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ:

सीडीएस का क्या मतलब है, बिल्कुल?

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या कार्य करता है?

- चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जिसमें सदस्यों के रूप में तीन सेवा प्रमुख होते हैं, की अध्यक्षता स्थायी रूप से सीडीएस द्वारा की जाती है।
- उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी न्यूनतम अंतर-सेवा तनाव बनाए रखना और भारतीय सेना की तीन सेवा शाखाओं के बीच अधिक परिचालन तालमेल को बढ़ावा देना होगा।
- वह रक्षा मंत्रालय के नव स्थापित सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) के निदेशक भी थे।
- सेवा प्रमुखों को अपनी सलाह को अपनी सेवाओं से जुड़े मामलों तक सीमित रखने की आवश्यकता होगी, और सीडीएस तीनों सेवाओं से जुड़े मामलों पर रक्षा मंत्री के एकल-बिंदु सैन्य सलाहकार के रूप में काम करेगा।
- स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष-प्रमुख और डीएमए के प्रमुख के रूप में, सीडीएस को अंतर-सेवा खरीद के संबंध में निर्णयों को प्राथमिकता देने की शक्ति दी गई है।
- इसके अतिरिक्त, तीनों प्रमुखों को सीडीएस से निर्देश प्राप्त हो सकते हैं।
- हालाँकि, उसके पास किसी भी सेना पर कमांड अधिकार का अभाव है।
- DoD (रक्षा विभाग) के भीतर, CDS सचिव का पद धारण करता है और समानों में प्रथम है। उसका अधिकार केवल राजस्व बजट तक ही सीमित है।
- इसके अतिरिक्त, वह न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी (एनसीए) के लिए सलाहकार क्षमता में काम करेंगे।

- सशस्त्र बलों और सरकार के बीच तालमेल: सीडीएस का काम रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक कर्मचारियों और सशस्त्र सेवाओं के बीच संचार में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए त्रि-सेवा सहयोग को बढ़ावा देने से परे है।
- 1947 से तीन सेवा मुख्यालयों (एसएचक्यू) को रक्षा विभाग के "संलग्न कार्यालयों" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। (डीओडी)।
- इसके कारण, फाइलों को मुख्य रूप से एसएचक्यू और डीओडी के बीच संचार के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है।
- सीडीएस की रक्षा मंत्री के पीएमए के रूप में नियुक्ति के साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी।
- संचालन में संयुक्तता: क्योंकि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी-सीओएससी (सीडीएस के अग्रदूत) की अध्यक्षता को तीन प्रमुखों के बीच अंशकालिक आधार पर घुमाया जाता है, यह अप्रभावी साबित हुआ है।
- अतीत में, अध्यक्ष COSC के पास महत्वपूर्ण त्रि-सेवा चिंताओं को दूर करने की शक्ति, क्षमता और प्रेरणा का अभाव था।
- सीडीएस त्रि-सेवा संगठन प्रबंधन को अब अपना पूरा ध्यान देने में सक्षम होगा कि वह "सीओएससी के स्थायी अध्यक्ष" हैं।
- थिएटर कमांड का संचालन : डीएमए की स्थापना से ज्वाइंट/थिएटर कमांड अधिक सक्रिय हो जाएगा।
- अंडमान और निकोबार कमान ने संयुक्त अभियानों के लिए एक प्रभावी मॉडल की स्थापना की, लेकिन राजनीतिक दिशा की कमी और सीओएससी की रुचि की कमी के कारण, यह संयुक्त कमान निष्क्रिय हो गई है।



- थिएटर कमांड द्वारा भूमि, समुद्र और विमानन बलों को तैनात करने के लिए ज्ञान और अनुभव वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इन नीतियों में से प्रत्येक को उनके विघटनकारी प्रभावों के कारण सीडीएस द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा।
- सामरिक बल कमान का प्रबंधन सीडीएस द्वारा किया जाएगा, जो परमाणु कमांड श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
- इस कार्रवाई से भारत की परमाणु निवारक की साख में उल्लेखनीय सुधार होगा।
- इसके अतिरिक्त, सीडीएस भारत के परमाणु सिद्धांत की तत्काल समीक्षा शुरू करेगा।
- सीडीएस की एक महत्वपूर्ण भूमिका सिकुड़ते रक्षा बजट के आगामी युग में अलग-अलग सेवाओं की पूंजी अधिग्रहण बोलियों को "प्राथमिकता" देना होगा।
- सीडीएस को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि "रक्षा रुपया" अच्छी तरह से युद्ध क्षमताओं पर खर्च किया जाता है, जिन्हें सेवा की जरूरतों को पूरा करने के बजाय राष्ट्रीय सैन्य शक्ति के लिए आवश्यक माना जाता है।

सीडीएस भूमिका पर पुनर्विचार क्यों?

- यह देखा गया है कि केवल सीडीएस की नियुक्ति ही पर्याप्त नहीं थी; भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से संबंधित कई चिंताएं हैं, साथ ही समानता और अन्य चीजों के प्रश्न भी हैं।

- सीडीएस द्वारा पहनी जाने वाली कई टोपी और डीएमए और डीओडी के बीच कर्तव्यों में ओवरलैप के साथ, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में भी एक द्वंद्व है।
- थिएटर कमांड के विकास के लिए निर्धारित आक्रामक समय सारिणी का पुनर्मूल्यांकन भी है, साथ ही साथ अपेक्षित संख्या में कमांड और उनकी संरचना भी है।

थिएटर कमांड की क्या स्थिति है?

- पहले सीडीएस को भारतीय सशस्त्र बलों को एकीकृत थिएटर कमांड में पुनर्गठित करने का महत्वाकांक्षी कार्य दिया गया था, जो पिछले 75 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य पुनर्गठन होगा और तीन सेवाओं के सहयोग के तरीके को गहराई से बदल देगा।
- तीनों सेनाओं के वाइस चीफ ने थिएटर कमांड पर व्यापक शोध किया, जिसमें भूमि आधारित पश्चिमी और पूर्वी थिएटर कमांड, मैरीटाइम थिएटर कमांड और एक एकीकृत वायु रक्षा कमांड शामिल थे। यह तय किया गया था कि सेना की उत्तरी कमान को शुरू में बाहर रखा जाएगा और फिर बाद में शामिल किया जाएगा।
- हालाँकि, अभी भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ असहमति है, जिसमें वायु रक्षा कमान के बारे में वायु सेना की चिंताएँ और अन्य बातों के अलावा, थिएटर कमांड के शीर्षक और रोटेशन शामिल हैं।
- सीडीएस की कमी और इस तथ्य के बावजूद चल रही असहमति के कारण प्रक्रिया रुक गई है कि आगे के अध्ययन अधिकृत थे और अब आयोजित किए जा रहे हैं।



आगे का रास्ता:

- संचालन प्राधिकरण के साथ एक सीडीएस की आवश्यकता होती है, और आवश्यक कानूनी संशोधनों के बाद, उन्हें थिएटर कमांडरों से रिपोर्ट प्राप्त होगी, जबकि सेवा प्रमुख व्यक्तिगत सेवाओं के कार्यों को बढ़ाने, प्रशिक्षित करने और बनाए रखने का प्रबंधन करते हैं।
- चूंकि सीडीएस का निर्माण रामबाण नहीं होगा, इसलिए भारत को इक्कीसवीं सदी की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए व्यापक सुधार करना चाहिए।



Guru Deekshaa IAS is happy to announce first ever kannada current affairs magazine for kannada medium aspirants of Karnataka. The three important thumb rules for any competitive exam are



Vijay Kumar G

Founder and Director
Guru Deekshaa IAS

- ✍ First-NCERT/STATE syllabus books which helps to develop your understanding on the subjects
- ✍ Second-Daily current affairs helped to build your further understanding of the events related to your examination, Apart from knowledge it build the personality of an individual which brings in confidence to face any examination.
- ✍ Third-Practice previous year question papers and mock test available in the market to train your mind as per the requirement of the examination.

Thousand miles of journey starts with single step, We at Guru Deekshaa have taken this first step towards empowering you to prepare for civil for services. Now its your turn to start preparation and achieve your dream of becoming IAS/IPS.

CALL US FOR MORE DETAILS

 **76 76 74 98 77**

JOIN OFFICIAL TELEGRAM FOR MATERIAL AND UPDATES

 @GURU_DEEKSHAAIAS



FOLLOW OUR INSTAGRAM FOR DAILY UPDATES

 GURUDEEKSHAA

